vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- ith;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 16 vad % 19 y[kuÅ] x:okj 21 vxLr 2025 l 27 vxLr 2025 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

क्या भारत संविधान निर्माताओं की उस अपेक्षा पर खरा उतर पाया है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह सवाल उठाया कि क्या भारत संविधान निर्माताओं की उस अपेक्षा पर खरा उतर पाया है, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच आपसी तालमेल होगा और दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों पर संविधान सभा में हुई चर्चा का उल्लेख किया। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए. एस. चंदुरकर भी शामिल हैं। मेहता ने पीठ को बताया कि कई बार की गई आलोचनाओं के उलट, राज्यपाल का पद केवल राजनीतिक आश्रय प्राप्त करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि संविधान के तहत उनके पास कुछ निर्धारित शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए संदर्भ पर अपनी दलीलें देते हुए कहा कि संविधान की संघीय संरचना को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में राज्यपालों की भूमिका और नियुक्ति पर गहन विचार–विमर्श हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत से यह जानना चाहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय–सीमा निर्धारित की जा सकती है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल से उन विधेयकों के बारे में सवाल किया था, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित होने के बाद लंबे समय से

राज्यपालों के पास लंबित हैं। कोर्ट ने उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया, जहां २०२० से कुछ विधेयक लंबित हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह केवल कानून के दायरे में अपनी राय देगी और तमिलनाडु मामले में आठ अप्रैल के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई थी। तमिलनाडु और केरल सरकारों द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श की विचारणीयता पर उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का जवाब देते हुए, पीठ ने कहा कि वह अपने परामर्शी क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगी, न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद १४३(१) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह जानने की कोशिश की थी कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार के लिए राष्ट्रपति के विवेकाधिकार हेतु समय–सीमा तय की जा सकती है। केंद्र ने अपनी लिखित दलील में कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय–सीमा निर्धारित करना संवैधानिक व्यवस्था को बाधित कर सकता है, क्योंकि यह सरकार के किसी अंग द्वारा ऐसी शक्ति का उपयोग होगा, जो संविधान ने उसे प्रदान नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में राज्यपाल की शक्तियों पर दिए गए फैसले में पहली बार यह व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने पांच पेज के परामर्श में शीर्ष अदालत से १४ सवाल पूछे और अनुच्छेद २०० और २०१ के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राय मांगी।

गंगा नदी के इतिहास पर शोध करवाएगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए आईआईटी–कानपुर के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर गंगा के अतीत को समझने और इसके संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत शुरू इस पहल का लक्ष्य नदी की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को संरक्षित करना है। इस शोध के तहत हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और फरक्का जैसे नौ प्रमुख स्थानों के लिए डिजिटल इंटरैक्टिव डिस्प्ले तैयार किए जाएंगे। ये डिस्प्ले स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति–निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। आईआईटी–कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजीव सिन्हा के अनुसार, यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई थी और इसका पहला

चरण पूरा हो चुका है। अब एनएमसीजी एक वेब–जीआईएस पोर्टल विकसित करने के लिए फंडिंग कर रहा है, जिसके माध्यम से यह डेटा आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। यह वेब–जीआईएस प्लेटफॉर्म एक उन्नत क्वेरी सिस्टम से लैस होगा, जो शोधकर्ताओं को जरूरत के हिसाब से डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। हालांकि, १९६५ से २०१९ के बीच यमुना नदी में तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन देखे गए। गंगा के चौनल बेल्ट और बाढ़ के मैदानों की चौड़ाई में कमी आई है, लेकिन नदी ने अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा है। वैज्ञानिकों ने उन क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए हैं, जहां गंगा को अपने पुराने प्रवाह को पुनर्जनन करने और भूमि उपयोग में सुधार के जरिए उसकी स्थिति को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। आईआईटी–कानपुर के विशेषज्ञ इस परियोजना को गंगा संरक्षण के लिए डेटा–आधारित नीतियों का एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए विशेष कदम

लखनऊ। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। इस सत्र में किसानों को १० लाख कुन्तल गेहूं बीज अनुदान पर दिया जाएगा। गन्ना उत्पादक किसानों को शीतकालीन गन्ने के साथ सहफसली खेती के लिए ७०८० कुन्तल राई और सरसों तथा १२५०० कुन्तल मसूर के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ६.५० लाख दलहनी और तिलहनी बीज मिनीकिट तथा भारत सरकार के सहयोग से ५.४१ लाख दलहनी बीज मिनीकिट भी निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई–लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी, जिससे वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके। इसके लिए किसानों को पहले से पोर्टल

पर पंजीकरण कराना होगा। तोरिया बीज मिनीकिट के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि ३१ अगस्त तय की गई है। इसके बाद १ सितम्बर से अन्य फसलों के बीज मिनीकिट के लिए पंजीकरण प्रारंभ होगा।

यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगेरू ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में यह भी कहा कि 'नाटो' में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को पुनः प्राप्त करने की यूक्रेन की उम्मीदें पूरी होना ''असंभव'' हैं। 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को एक लंबी बैठक हुई। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते

हुए ट्रंप ने जेलेंस्की द्वारा मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाले प्रयास में भाग लेने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया था। पिछले सप्ताह अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विचार के लिए तैयार हैं लेकिन मंगलवार को 'फॉक्स न्यूज चौनल' के 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा।

सम्पादकीय

नजरअंदाज करना अब भारी पड़ रहा

डॉनल्ड ट्रंप के प्रमुख टैरिफ संबंधी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जो सख्त बातें कहीं हैं, उनका संकेत है कि निकट भविष्य में अमेरिका से भारत के रिश्ते बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। यानी ट्रंप प्रशासन के टैरिफ की मार भारत को लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। नवारो ने कहा कि भारत अगर चाहता है कि अमेरिका उससे रणनीतिक सहभागी जैसा व्यवहार करे, तो उसे अपना व्यवहार सुधारना होगा। उसे रूस से तेल खरीदने का "अवसरवाद" छोड़ना होगा। नवारो ने नाराजगी जताई कि ऐसा करने के बजाय अब भारत रूस और चीन से अपने संबंध और बढ़ा रहा है। मतलब साफ है। अमेरिका की सख्ती जारी रहने वाली है। यही वजह है कि कारोबार जगत में इंडिया१ का जुमला चल निकला है। इसके पहले चीन१ की बात चर्चित हुई थी, जब अमेरिकी सरकार ने चीन के खिलाफ व्यापार कार्रवाई शुरू की। तब अमेरिकी कंपनियों ने चीन से किसी अन्य देश में अपने कारखाने ले जाने शुरू किए। उसका कुछ लाभ भारत ने भी उठाया। मगर अब भारत निशाने पर है। तो खबरों के मुताबिक कई कंपनियां अपने कारखाने भारत से बांग्लादेश, कंबोडिया या वियतनाम ले जाने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि भारत में कारखाना उत्पादन का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी बाजार रहे हैं। पिछले साल भारत के कुल निर्यात का १८ फीसदी हिस्सा अमेरिका गया था। अब ये बाजार भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिकूल होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि चूंकि भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार कमजोर है और अन्य देशों में तुरंत बाजार हासिल करना आसान नहीं है, तो कंपनियां उन देशों में जाने पर विचार कर रही हैं, जिन पर लगा टैरिफ भारत से कम है। इसका असर अभी से भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्रों में महसूस किया जाने लगा है। आम राय है कि आने वाले महीने और भी ज्यादा चुनौती भरे होंगे। भारत के लिए यह बुरी खबर है। मगर चीन१ की जिस पृष्ठभूमि पर भारत के आगे बढ़ने की आस जोड़ी गई थी, उसमें यह जोखिम पहले से मौजूद था। उसे नजरअंदाज करना अब भारी पड़ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी मिशन–2027 का आगाज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक प्रयोगशाला है जिसमें जात, धर्म, सांप्रदाय लगभग हर तरह के राजनीतिक समीकरण पर प्रयोग होता है। साल २०१४ का लोकसभा चुनाव, २०१७ का विधानसभा चुनाव, २०१९ का लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक बात तो साफ ही कर दिया की यूपी में योगी के टक्कर का कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। पीडीए यानी की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। इस चुनाव में सपा ३७ लोकसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी मिशन–२०२७ का आगाज करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर २१ अगस्त को अलीगढ़ में बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक शामिल होंगे। वक्त ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह की तूती बोलती थी। कल्याण सिंह का जन्म पांच जनवरी १९३२ को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ। कल्याण सिंह के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। उनके पुत्र राजवीर सिंह बीजेपी

से एटा से सांसद रह चुके है। अब कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इसके साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने और अखिलेश के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने की कवायद में लगी है। २१ अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ८० हजार से अधिक लोगों को एकत्रित करने की योजना बनी है। जिसके लिए कल्याण सिंह के प्रभाव वाले ४० जनपदों के साथ–साथ प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे। बाबरी के विवादित ढांचे के विध्वंस प्रकरण के लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्खास्त कर दिया। उस वक्त त्यागपत्र देने के बाद कल्याण सिंह ने कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राममंदिर के नाम पर कुर्बान हुई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उनकी राजनीति का दूसरा चेहरा मंडल और मंदिर के बीच संतुलन साधने का था। मंडल फैसले से राजनीति जातीय खांचों में बंटी, तब उन्होंने पिछड़ों–दलितों को भाजपा से जोड़कर 'सोशल इंजीनियरिंग' का नया अध्याय लिखा। इससे भाजपा का जनाधार व्यापक हुआ और वे हिंदुत्व के साथ सामाजिक समीकरणों के शिल्पकार भी बने।

ईपीएफओः कर्मचारियों को १५,००० रुपये तक मिलेगा प्रोत्साहन

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लालकिले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबी आरवाई) का औपचारिक शुरुआत किया। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना और

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पहली बार ईपीएफओ में पंजीत होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम १५,००० तक का प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त ६ माह की सेवा पूरी होने पर और दूसरी किस्त १२ माह की सेवा के साथ वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रदान की जाएगी। नियोक्ताओं को भी प्रति अतिरिक्त रोजगार ३,००० रुपये प्रतिमाह तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो सामान्य क्षेत्र में २ वर्षों और विनिर्माण क्षेत्र में ४ वर्षों तक मिलेगा। प्रोत्साहन राशि वेतन के स्लैब के अनुसार १,००० से ३,००० रुपये प्रतिमाह तक होगी। यह योजना १ लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और रायबरेली जिलों में ३७,९२६ पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, जिनमें से ७,०८७ सक्रिय योगदानकर्ता हैं और ५ लाख से अधिक कर्मचारी सक्रिय यूएएन धारक हैं। क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले चार महीनों में १.८८ लाख से अधिक दावे निस्तारित कर ४६८ करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। योजना का लाभ उठाने के लिए ५० से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो और ५० या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को न्यूनतम पांच नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए १८ अगस्त को **pmvbry-epfindia-gov-in** पोर्टल शुरू किया गया है।

प्रदेश में कहीं भी उर्वरक की दिक्कत नहीं, कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त

लखनऊ। योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। कृषि विभाग ने सभी १८ मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी। खरीफ सत्र २०२४ में इस अवधि (१८ अगस्त) तक ३६.७६ लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक ४२.६४ लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की कि खाद का भंडारण न करें। जितनी आवश्यकता है, उतना खाद लें, जब–जब आवश्यकता है, तब–तब खाद लें। हर जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ है। किसी भी परेशानी की स्थिति में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने उर्वरक की ओवररेटिंग, कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने जनपद में तैनात अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षण करने, किसानों से संवाद स्थापित करने और समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।ंषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अभी तक अधिक खाद वितरण किया जा चुका है। विगत वर्ष २७.२५ लाख मीट्रिक

टन यूरिया वितरण हुआ था, इस वर्ष अभी तक ३१.६२ लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। डीएपी २०२४ में वितरण ५.२८ लाख मीट्रिक टन का रहा, इस वर्ष यह बिक्री ५.३८ लाख मीट्रिक टन हुई। एनपीके उर्वरक (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटेशियम मिश्रण) का वितरण विगत वर्ष २.०७ लाख मीट्रिक टन रहा, इस वर्ष २.३६ लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) ०.२५ लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष इस वर्ष ०.४६ लाख मीट्रिक टन वितरित हुआ। वहीं एसएसपी (सिंगल सुपर फ स्फेट) का वितरण २०२४ में १.६१ लाख मीट्रिक टन रहा, इस वर्ष किसानों को २.७६ लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। यूरियाः' १८ अगस्त तक प्रदेश में ३७.७० लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता रही। इसमें से ३१.६२ लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों द्वारा की जा चुकी है। डीएपीरू' १८ अगस्त तक ६.२५ लाख मी. टन की उपलब्धता रही, जिसमें से ५.३८ लाख मी. टन की खरीद किसानों ने कर ली है। एनपीकेरू' १८ अगस्त तक ५.४० लाख मीद्गटन की उपलब्धता रही। इसमें से २.३६ लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों ने कर ली। खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य फसल धान में टॉप–ड्रेसिंग हेतु प्रतिदिन औसतन ४६५६४ मीद्गटन यूरिया की खपतध् बिक्री हो रही है। गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष १६.०४ः (मात्रा ४.३७ लाख मीद्गटन) अधिक यूरिया उर्वरक की बिक्री हुई है।

यूपी की मिसाइल ने दुश्मनों के अड्डों को किया ध्वस्तः सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा भवन परिसर के सामने तिरंगा फहराया। उसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद और बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में बनी मिसाइल ने दुश्मन के अड्डों को तहस–नहस कर दिया। यूपी में रोजगार को लेकर कहा कि यहां का वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट दुनिया में धूम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछो। स्वदेशी म डल से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश का ओडीओपी मॉडल दुनिया में धूम मचा रहा है। देश का पैसा देश में लगेगा। यहां का पैसा यहीं लगना चाहिए। इसमें हस्तशिल्प से लेकर किसान तक खुश होंगे। इसे हमें समेटना है। तकनीक और डिजाइन साथ बाजार के अनुरूप काम करना होगा। पीएम ने इसीलिए लोकल फ र वोकल का आह्वान किया है। मेक इन इंडिया से देश खुशहाल होगा। सीएम योगी ने आगे कहा, "प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसान खुशहाल होंगे।" मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले यहां पर गुंडागर्दी चरम पर थीय व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज सुरक्षा का नया म डल विकसित किया गया है। आज यहां का युवा अपना लोहा मनवा रहा है। यह राज्य निवेश का ड्रीम स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी शक्ति और ऊर्जा को पहचान कर आगे बढ़ने वाले देश ही आगे बढ़ते हैं। पुलिस बल में महिलाओं को ३३ फीसदी से ५० फीसदी तक आरक्षण देने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। यूपी में पुलिस बल की भर्ती में ६०,२०० में से १२ हजार से अधिक महिला भर्ती हुई है। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। यूपी विध ानसभा में काम काज का माहौल कम होता है, ऐसा लोगों का कहना होता है। रात भर यूपी विधानसभा में लगातार ३६ घंटे चर्चा हुई। इसमें सतत विकास पर चर्चा हुई, जो आम आदमी की जरूरत है। योगी ने कहा कि हाल में देश ने पीएम मोदी के नेतृत्व में अ परेशन सिंदूर की शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं सभी सैनिकों को नमन करता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में देश की अखंडता को मजबूत किया है। जब सैनिक देश की सीमाओं पर होते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। इसी पर सु ढ़ भारत का निर्माण हो रहा है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का मतलब अपने कर्तव्यों के प्रति संकल्पित होने का अवसर है। अगर हर नागरिक दायित्व का निर्वहन करने लग जाए तो पीएम का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने में देर नहीं लगेगी। भारत २०४७ में विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया की बड़ी ताकत होगी।

२०१४ में हुई हत्या के एक मामले में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

लखनऊ। मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने २०१४ में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में चार भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुध ावार को यह जानकारी दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने मंगलवार को नवाब, इंसार, कादिर और इस्लाम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ३०२ के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर ३०,००० रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि १४ जुलाई २०१४ को शामली जिले के शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवा गांव में पुरानी रंजिश में किए गए हमले में इकराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के सिलसिले में चारों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

तीन जनपदों के जिला कृषि अधिकारी सस्पेंड, विभाग में मची खलबली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पदीय दायित्वों का निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन जिलों के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही दस अन्य लोगों को नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोटिस उन लोगों को जारी की जा रही है, जिनके पास खेत कम है और उन्होंने खाद ज्यादा उठा ली है। यहां कृषि भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिन जिला कृषि अधि ाकारियों को निलंबित किया गया है। उनमें मंजीत कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी बलरामपुर प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा और अशोक प्रसाद मिश्र जिला कृषि अधिकारी श्रावस्ती शामिल है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खाद की कालाबाजारी को लेकर रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाद की कमी पर सवाल उठाए जाने को लेकर कषि मंत्री ने कहा कि अखिलेश को बोलने का कोई हक नही है। उनके समय मे खरीफ सीजन में केवल ६१.४५ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुवाई हुई थी जबकि किसानों को समय से उन्नत बीज खाद पानी सिंचाई संसाधनों में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरुप वर्ष २०२३ २४ में खरीफ के फसलों का आच्छादन बढ़कर १०१.प८ हेक्टेयर हो गया है। २०२४ में यह क्षेत्रफल १०५.६३ लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ३६००० किसानों की ऋण माफी की थी। कृषि मंत्री ने बताया कि महाराजगंज में जून माह के दौरान १८६ लोग ऐसे पाए गए हैं। जिन्होंने एक मीट्रिक टन से लेकर २.३७५ मीट्रिक टन तक यूरिया का क्रय किया गया है। इन लोगों के द्वारा चार बार से लेकर १३ बार तक खाद का क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जांच जोत के रकवे के साथ कराई जा रही है। जांच के दौरान यदि

कालाबाजारी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में भी कई लोगों के द्वारा एक मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का क्रय चार बार से लेकर २० बार में किया गया है। उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ५.६ ० लाख मीट्रिक टन यूरिया ३.८७ लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं ३ लाख मीट्रिक टन एनपीके २.५ लाख मीट्रिक टन एसपी ०.६३ लाख मीट्रिक टन को मिलाकर कुल १५. ६१ लाख मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में २.५ लाख मीट्रिक टन यूरिया १.६४ लाख मीट्रिक डीएपी एवं ०.८ लाख मैट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में ३.८७ लाख मीट्रिक टन यूरिया १.६३ लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं २.१२ लाख मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में २४ रैंक यूरिया की १२ रैंक डीएपी ट्रांजिट में है। जो अगले तीन से चार दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। प्रतिदिन १० से १२ रैंक यूरिया की एवं ५ से ६ रैक डीएपी की प्रदेश को उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, इसके लिए कृषि विभाग अभियान चलाएगा। १५ सितंबर को हम लोग पोर्टल खोलने जा रहे है। जिस पर किसानों से आवेदन माँगे जाएँगे। उन्होंने कहा कि २०१४ में मोदी सरकार बनने के बाद से यूरिया और डीएपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।ेंषि मंत्री ने कहा कि इस बार दलहन और तिलहन का रकबा गेहूं की अपेक्षा ज्यादा बढ़ने पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं की अपेक्षा किसानों को दलहन और तिलहन से अच्छा लाभ मिलता है हम १२ लाख ८० हजार ३५० पैकेट किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कमियाँ पाई जाने पर ११६६ दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए गये और ६३ लोगों के खघ्लिाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

दफ्तर से निकलकर रोजाना फील्ड में जाएं अधिकारी, उपभोक्ताओं से मिलें : एके शर्मा

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि वे दफ्तरों तक सीमित न रहकर फील्ड में उतरकर अपनी सक्रियता दिखाएं। यह भी हिदायत दी कि अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखें और

उपभोक्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। एके शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा एवं संतोष ही हमारी प्राथमिकता है। सरकार की मंशा है कि हर घर तक निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो, ऊर्जा मंत्री ने विशेष रूप से १६१२ उपभोक्ता सेवा हेल्पलाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस नंबर पर आने वाली हर शिकायत को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि शिकायतों की अनदेखी या लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल, पंकज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी एमडी व जनपद स्तरीय अधिकारी अ नलाइन मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बार–बार खराब होते हैं, उन्हें चिन्हित कर तुरंत ट्रांसफार्मर उच्चीत किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को बार–बार बिजली बाधित होने की परेशानी से राहत मिले। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता लाकर उपभोक्ताओं का भरोसा जीता जाए।

उर्वरक की कमी को लेकर अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर किसानों को निराश करने और राज्य में उर्वरक संकट को गहरा करने का मंगलवार को आरोप लगाया। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर 'हैशटैग' 'अयोध्या–खाद–किल्लत' से की गयी एक पोस्ट में कहा, कह गये ऐसा भाजपाई कलियुग आएगा कृषक खाएगा लाठी–डंडा खाद का संकट गहरायेगा। उन्होंने ३१ सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें एक पुलिसकर्मी लाठी लिए हुए लोगों की भीड़ को नियंत्रित कर रहा है। इस बीच, अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल

टीकाराम फुंडे ने इन दावों को खारिज करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो सोमवार का है लेकिन ''लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भीड़ के कारण कुछ लोगों ने कतार तोड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने अनुशासन बनाए रखने के लिए केवल हल्की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य रही और किसानों को कोई कठिनाई नहीं हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे जिले में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, अब तक अयोध्या में ४३,००० मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया जा चुका है जो पिछले साल से ज्यादा है। सितंबर के अंत तक यह आंकड़ा पिछले साल के रिक र्ड को पार कर जाएगा।

घर में सोए युवक की धारदार हथियार से हत्या

सहारनपुर। जिले में नकुड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में २५ वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने पीटीआई– को बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव सांपला बेगमपुर निवासी अंकित (२५) का शव रविवार सुबह उसके घर में चारपाई से आधा लटका हुआ मिला। जैन ने बताया कि शनिवार रात अंकित अपने चचेरे भाई अतुल के साथ घर की छत पर सोने गया था और रविवार तड़के करीब चार बजे अंकित का शव नीचे के कमरे में चारपाई से आधा नीचे लटका हुआ मिला। उन्होंने बताया कि अंकित की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था और कमरे के अंदर व बाहर खून बिखरा हुआ था। अंकित के पिता अशोक ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उन्होंने शोर मचाकर परिजनों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद

पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि अंकित छत से नीचे कमरे में कैसे आया और किसने उसकी हत्या की। अंकित के चचेरे भाई अतुल ने बताया कि रात एक बजे उससे बात करते हुए वह सो गया था और उसे कुछ पता नहीं चल पाया।

निष्कासित विधायक पूजा पाल पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी पर एक और मुकदमा दर्ज

लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) से हाल में निष्कासित विधायक पूजा पाल के बारे में सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सैरपुर थाने में उमेश यादव नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने बताया कि यादव ने फेसबुक और एक्स सहित सोशल मीडिया मंचों पर चायल सीट से

सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणियां 'पोस्ट' की थीं। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा, अभद्र टिप्पणियों के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के एक पंचायत सदस्य की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच जारी है। इस मामले पर यादव के खिलाफ यह दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले, १७ अगस्त को कौशांबी जिले के पिपरी थाने की पुलिस ने भी पाल के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पूजा पाल को हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथित सराहना करने के बाद सपा से निष्कासित कर दिया गया था।

धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर अगस्त २०२५ से ३१ मार्च, २०२६ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा-जयवीर सिंह

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सप्ताह में एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अगस्त २०२५ से शुरू होकर ३१ मार्च, २०२६ तक कराये जायेगें। यह कार्यक्रम लोक कलाकारों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा रोजी रोटी के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए प्रति स्थल प्रतिदिन कलाकार का मानदेय ४० हजार रूपये एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं के लिए ०८ हजार रूपये दिये जायेंगे, इस प्रकार प्रति स्थल ४८००० रूपये व्यय अनुमानित है। यह जानकारी आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्थल पर लगभग १५ दिन तक कार्यक्रम कराया जायेगा। इस प्रकार २१ स्थलों पर कार्यक्रम कराये जाने पर लगभग ३५२.८० लाख रूपये (तीन करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) का व्यय अनुमानित है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम कराये जाने से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का बड़ी संख्या में आगमन होगा, जिससे

स्थानीय लोगों को रोजगार एवं राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थल चिन्हित कर दिये गये हैं। जिसमें कुसुमवन सरोवन मथुरा, झांसी का किला, रामघाट चित्रकूट, सुबह-ए-बनारस वाराणसी, त्रिवेणी घाट प्रयागराज, कुड़िया घाट/लोहिया पार्क/रायउमानाथ बली/जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ, शुक्रतीर्थ मुजफ्फरनगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, राम की पैड़ी अयोध्या, समौर बाबा धाम फिरोजाबाद, सीता समाहित स्थल भदोही, बटेश्वर धाम आगरा, परमेश्वरी धाम आजमगढ़, विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर विन्ध्याचल, प्रेम मंदिर वृन्दावन, नैमिषारण्य धाम सीतापुर, देवीपाटन मंदिर बलरामपुर, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, शाकुंभरी देवी सहारनपुर तथा शीतलाधाम मंदिर मैनपुरी शामिल है। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से विलुप्त होती जा रही गीत संगीत एवं लोक संगीत को संरक्षित करने का भी कार्य होगा तथा लोक कलाकारों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खासतौर से संसेंति विभाग लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रतिबद्ध है। इन कलाओं को सुरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी उद्देश्य पूरा होगा। साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा।

नहीं जायेगी अब्बास अंसारी की विधायकी, निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत के फेसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब उनकी विधायकी नहीं जायेगी। दरअसल, भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से २ साल की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन ने सुनाया है। फैसले के बाद अब अंसारी की विधायकी बहाल हो जायेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। वर्ष २०२२ के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए रहे अब्बास अंसारी ने चुनावी सभा के दौरान ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने जैसे शब्द कहे थे। इसे भड़काऊ बयान मानते हुए उन पर हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसके बाद मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा १५३-ए और १८६ के तहत अपराध के लिए अब्बास अंसारी पर दो साल कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया

था। इसी फैसले के कारण १ जून को विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था यानी उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने उनके चुनाव एजेंट मंसूर को छह महीने जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी थी, जबकि छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक

सीवर टैंक में गिरने से दो श्रमिकों की मौत, आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-११५ स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन में गत शनिवार को सीवर टैंक में गिरने से दो श्रमिकों की मौत के मामले में दो आरोपी ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सेक्टर-११३ के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि जनपद अलीगढ़ के मऊआखेड़ा गांव निवासी बृजेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार को उनके भाई खुशाल (२४) और ताऊ का बेटा विकास (२६) ठेकेदार अजीत और पुष्पेंद्र के कहने पर सेक्टर-११५ में सीवर लाइन की सफाई के लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद अमित नाम के व्यक्ति का फोन आया कि खुशाल और विकास की सीवर में डूबने से मौत हो गई है। बृजेश का आरोप है कि ठेकेदारों ने दोनों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया था। ठेकेदार की लापरवाही के कारण दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी ठेकेदार पुष्पेंद्र कुमार और अजीत को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह पंपिंग स्टेशन नोएडा प्राधिकरण का है और जल विभाग ने इसका काम ठेकेदार को सौंपा है। वहीं, जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने दावा किया कि सुरक्षा उपकरण व मानकों का पालन किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि मृतकों के परिजन को छह-छह लाख रुपये का मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए ५०-५० हजार रुपये दिए गए हैं। साथ ही एक मृतक की पत्नी को प्राधिकरण में संविदा पर नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। खुशाल और विकास दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों रोजी-रोटी की तलाश में यहां आए थे। बृजेश ने बताया कि खुशाल की दो बेटियां हैं। उसकी पत्नी सात महीने की गर्भवती भी है। इस बीच, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ड . लोकेश एम ने कहा कि यह स्पष्ट निर्देश हैं कि बगैर सुरक्षा उपकरण के श्रमिकों से काम न कराया जाए। ऐसे में यह हादसा चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। जल विभाग के महाप्रबंधक से रिपोर्ट मांगी गई है।

आखिर कैसे ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी.. कहां थी १३ दिन, पुलिस ने खोली सारी परतें

लखीमपुर खीरी। भोपालः नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच से १३ दिनों तक लापता रही अर्चना तिवारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। भोपाल रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि अर्चना ७-८ अगस्त की रात को गायब हुई थी और ११-१२ दिन बाद नेपाल सीमा से उसे बरामद किया गया। कटनी की छात्र नेता रही अर्चना पर परिवार शादी का दबाव बना रहा था, जबकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना की दोस्ती इंदौर में शुजालपुर के सारांश नामक युवक से हुई थी। दोनों उस दिन एक ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। परिवार ने अर्चना का रिश्ता एक पटवारी से तय किया था, जिसके लिए उसे पढ़ाई छोड़ने का दबाव डाला जा रहा था। अर्चना ने सारांश के साथ हरदा में एक ढाबे पर मुलाकात की और भागने की योजना बनाई। बाद में योजना रद्द कर गायब होने की साजिश रची। अर्चना ने सोचा कि जीआरपी गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से नहीं लेगी। उसने ऐसी जगह से भागने की योजना बनाई जहां सीसीटीवी न हो। तेजेन्द्र नामक व्यक्ति ने नर्मदापुरम में उसे कपड़े दिए। अर्चना ठ३ कोच से। २ कोच में गई और बिना सीसीटीवी वाले आउटर से निकली। उसने तेजेन्द्र को अपना मोबाइल बागतवा के जंगलों में फेंकने को कहा। इसके बाद वह सारांश के साथ कार से चली गई। उसी रात तेजेन्द्र को दिल्ली पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामले में पकड़ लिया। अर्चना ने जानबूझकर ट्रेन में सामान छोड़ा ताकि लगे कि वह कहीं गिर गई।

उसका मोबाइल भी जंगल के पास बंद हो गया। वह सारांश से व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी, जिससे पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) नहीं मिला। पुलिस ने जब सारांश को हिरासत में लिया, तब सारी परतें खुलीं। दोनों ने टोल नाकों से बचने की कोशिश की और अर्चना ने बीच में नया मोबाइल भी लिया। मामला मीडिया में उछलने के बाद अर्चना ने दूसरे राज्य में जाने की योजना बनाई। वह पहले हैदराबाद गई, फिर बस से दिल्ली होते हुए काठमांडू चली गई। सारांश ने अपना मोबाइल इंदौर में छोड़ दिया था और वह वापस लौट आया था। पुलिस ने सारांश को हिरासत में लेकर अर्चना को नेपाल सीमा पर बुलाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसे दिल्ली के रास्ते फ्लाइट से भोपाल लाया गया। पुलिस को पता चला कि तेजेन्द्र और सारांश इंदौर में पड़ोसी थे और उनके बीच पैसे का लेन-देन था। कांस्टेबल राम तोमर का गुमशुदगी में कोई रोल नहीं था, लेकिन वह अर्चना को बार-बार फोन करता था और उसका टिकट बुक करवाता था। अर्चना इससे परेशान थी। उसने सारांश के साथ प्रेम संबंध से इनकार किया। परिवार के शादी के दबाव से तंग होकर अर्चना ने यह पूरी साजिश रची। वह पूरी तरह होश में थी और इस योजना की मुख्य सूत्रधार वही थी, जिसमें तीन लोगों ने उसका साथ दिया।

रूस पर दबाव के लिए भारत पर ट्रंप का प्रतिबंध, व्हाइट हाउस का बड़ा दावा!

नई दिल्ली। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला अप्रत्यक्ष रूप से रूस पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाने के लिए था। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि ट्रम्प ने भारत की टैरिफ दर को दोगुना करके ५० प्रतिशत कर दिया है – मौजूदा २५ प्रतिशत के ऊपर २५ प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया है। उन्होंने इस कदम को रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों को निशाना बनाकर मास्को पर दबाव बनाने की प्रशासन की रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने आगे कहा ष्राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जनता पर भारी दबाव डाला है। जैसा कि आपने देखा है, उन्होंने भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम भी उठाए हैं,ष उन्होंने आगे कहा कि उनका उद्देश्य मास्को पर ष्दूसरा दबाव' डालना था। उन्होंने आगे कहा 'उन्होंने दूसरों के इस विचार का मजाक उड़ाया है कि हमें किसी भी बैठक से पहले एक महीने और इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रपति आगे बढ़ना चाहते हैं, और वह इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। यह ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की मेजबानी के कुछ ही दिनों बाद आया है, जहाँ दोनों नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित त्रिपक्षीय वार्ता की दिशा में प्रगति का संकेत दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए ढ़ हैं। लेविट ने कहा 'राष्ट्रपति आगे बढ़ना चाहते हैं और वह इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं... नाटो महासचिव सहित सभी यूरोपीय नेताओं के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद, वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक शानदार पहला कदम है। और यह अच्छी बात है कि ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे, और राष्ट्रपति को उम्मीद है कि ऐसा होगा। उन्होंने आगे कहा, ष्मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और ट्रंप प्रशासन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मिलकर इस

द्विपक्षीय वार्ता को संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं।' लेविट ने बताया कि ट्रंप के शांति के प्रयासों के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात के ४८ घंटे के भीतर ही यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस पहुँच गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो इस संघर्ष को टाला जा सकता था, तो लेविट ने प्रशासन के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति अक्सर कहते हैं कि अगर वह पद पर होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता और पुतिन ने इसकी पुष्टि की है।' लेविट ने पुष्टि की कि पुतिन ने भी इस ष्टिकोण को स्वीकार किया है, जिससे ट्रंप के लंबे समय से चले आ रहे इस दावे को बल मिलता है कि उनके राष्ट्रपति रहते युद्ध छिड़ने से बचा जा सकता था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में यह भी कहा कि 'नाटो' में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को पुनः प्राप्त करने की यूक्रेन की उम्मीदें पूरी होना ''असंभव'' हैं। 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को एक लंबी बैठक हुई। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की द्वारा मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाले प्रयास में भाग लेने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया था। पिछले सप्ताह अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विचार के लिए तैयार हैं लेकिन मंगलवार को 'फॉक्स न्यूज चौनल' के 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा।

जिला अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा के सेक्टर ३६ स्थित जिला अस्पताल में सोमवार रात को एक नर्सिंग अधिकारी से छेड़खानी करने के आरोप में एक यू–ट्यूब चौनल के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना सेक्टर ३६ के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता जिला अस्पताल के महिला वार्ड में नर्सिंग अधिकारी है और उसने इस घटना के संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, महिला का आरोप है कि सोमवार देर रात शराब के नशे में धुत्त मनोज शर्मा नाम का व्यक्ति मेडिसिन के महिला वार्ड में आया और पीड़िता को जबरदस्ती वार्ड के पीछे ले जाने लगा तथा उसके साथ बदसलूकी एवं छेड़खानी की। सिंह ने शिकायत के हवाले से बताया कि महिला का शोर सुन वार्ड प्रभारी और सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया तथा इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि आरोपी यू–ट्यूब पर एक समाचार चौनल चलाता है और पूर्व में भी अस्पताल के कर्मचारियों को परेशान कर चुका है।

शपथपत्रों की पावती पर गौर करे इनकार करने वाला निर्वाचन आयोग : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिये गये शपथपत्र प्राप्त नहीं होने का दावा करने वाला आयोग उन हलफनामों की प्राप्ति की पावती पर गौर करे। यादव ने 'एक्स' पर कहा, ''जो निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिये गये हलफनामे नहीं मिले हैं, वह हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख ले।'' उन्होंने कथित रूप से डाक विभाग द्वारा दी गयी रसीदों की तस्वीरें भी टैग करते हुए लिखा, ''इस बार हम मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग शपथपत्र दे कि यह जो डिजिटल रसीद हमें भेजी गयी है वह सही है, नहीं तो 'निर्वाचन आयोग' के साथ–साथ 'डिजिटल इंडिया' भी शक के घेरे में आ जाएगा।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''भाजपा जाए तो सत्यता आए।'' यादव का यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एक प्रेसवार्ता में वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों को गलत बताये जाने के बाद आया है। यादव ने इससे पहले एक्स पर एक अन्य संदेश में कहा था कि सपा ने वोट डकैती के १८ हजार शपथ पत्र आयोग को दिये थे लेकिन कार्रवाई शून्य है।

हाईकोर्ट ने निराधार व भ्रामक याचिकाएं दाखिल करने वाले अधिवक्ता को लगाई फटकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की तीसरी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न केवल याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि आवेदक के अधिवक्ता की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट का कहना है कि आवेदक के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को उचित कानूनी परामर्श नहीं दिया और लगातार निराधार व भ्रामक याचिकाएं दाखिल कर न्यायालय का समय व्यर्थ किया। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता विकास चंद्र तिवारी के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की लापरवाही न्यायिक व्यवस्था के लिए बाधक है। लगातार तीन अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल करना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार–बार ऐसी अर्जी दाखिल करने से न्यायिक अनुशासन प्रभावित होता है और वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। उक्त आदेश कृष्ण पहल की एकलपीठ ने संजीव कुमार उर्फ संजय की याचिका खारिज करते हुए पारित किया। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि आवेदक पिछले तीन वर्षों से ट्रायल कोर्ट से बचता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कारतरे और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य (१९७६) मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि कोई व्यक्ति यदि कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए छिपता है, चाहे वह अपने ही घर में क्यों न हो, तो वह कानून की नजर में 'फरार' माना जाएगा। दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया। मामले के अनुसार याची ने अपने सह–आरोपियों राजपाल, नवनीत, भोला, स्वेता और शिवानी के साथ मिलकर ८ मार्च २०२२ को शाम करीब ५ बजे शिकायतकर्ता पर हमला किया। इस दौरान सह–आरोपी भोला ने गला दबाने का प्रयास किया और दूसरे सह–आरोपी राजपाल ने चाकू से वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद याची के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, मुरादाबाद में मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने पाया कि पहले की दो अग्रिम जमानत अर्जियां आरोपपत्र दाखिल होने से पहले दाखिल की गई थीं और उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन आरोपपत्र दाखिल होने (०१ अक्तूबर २०२४) के बाद तीसरी अर्जी दाखिल करना न्याय प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है, इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

रामभद्राचार्य ने बांके बिहारी मंदिर पर नियंत्रण करने की उप्र सरकार की योजना का विरोध किया

मथुरा। प्रख्यात रामकथा वाचक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पर मंगलवार को सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मस्जिदों और चर्च के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता तो मंदिरों के मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के लिए न्यास स्थापित करने और बांके बिहारी गलियारा विकसित करने की राज्य सरकार की योजना पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने यह टिप्पणी की। वृन्दावन के तुलसी

पीठ छत्तीसगढ़ कुंज में पिछले एक सप्ताह से श्रीमद्भागवत कथा पाठ कर रहे रामभद्राचार्य ने कहा, '' मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार किसी मस्जिद या चर्च पर नियंत्रण नहीं कर सकती तो मंदिर को ही क्यों अपने नियंत्रण में लेकर उसका कोष हड़पना चाहती है।'' रामभद्राचार्य ने सरकार द्वारा मंदिर का न्यास बनाए जाने पर भी अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता को एक अध्यादेश के माध्यम से एक न्यास की स्थापना एवं गलियारे के निर्माण का कारण बताया है।

योगी सरकार के प्रयासों से देश-विदेश में बन रहे रोजगार के अवसर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल कर रही है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने जिस दूरदर्शिता से रोजगार सृजन की बहुआयामी रणनीति अपनाई है, रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की नीति अब सिर्फ स्थानीय नौकरियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की शुरुआत की है। मिशन के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगार के अवसरों को पता लगाना, स्किल गैप का अध्ययन कर उसको दूर कराना, रोजगार कार्यक्रम संचालित करना, करियर काउंसलिंग कराना तथा राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों एवं अल्प रोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रदान करना है, जिससे घरेलू एवं विदेशी प्लेसमेंट द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जाएगा तथा बाजार मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इस अभियान को और विस्तार देते हुए प्रदेश सरकार ने जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी नर्सों, केयर गिवर्स, ड्राइवरों और निर्माण श्रमिकों की मांग प्राप्त की है। इसमें लगभग १.५० लाख रुपये तक का वेतन मिलेगा, साथ ही खाड़ी देशों से भी विभिन्न सेक्टर की रिक्तियों की प्राप्ति सम्भावित है। श्रम विभाग इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक और बेहतर वेतनमान वाली नौकरियां मिल सकें। यह पहल युवाओं को विदेश जाने का सुरक्षित और कानूनी विकल्प उपलब्ध कराकर अवैध माध्यमों पर भी रोक लगाने में सहायक है। रोजगार सृजन को लेकर प्रदेश सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है। १ अप्रैल २०१७ से लेकर ३० अप्रैल २०२५ तक सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित १०,८३०

रोजगार मेलों के माध्यम से १३,६४,५०१ अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। ये मेले राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया और युवाओं को मौके पर ही चयनित कर नौकरी दी। इससे न केवल युवाओं को अवसर मिले बल्कि कंपनियों को भी प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति उपलब्ध हुई। इस मिशन के तहत अब तक ५,६७८ श्रमिकों को इजरायल में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं, १,३८३ और निर्माण श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है। इस प्रयास से राज्य में न केवल विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अनुमान है कि इजरायल भेजे गए श्रमिकों से प्रदेश को लगभग १,००० करोड़ रुपये कारेमिटेंस प्राप्त हो सकता है, जो 'वन ट्रिलियन ड लर अर्थव्यवस्था' के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी सरकार का मानना है कि केवल नौकरी उपलब्ध कराना पर्याप्तनहीं है, बल्कि युवाओं को सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत सेवायोजन विभाग द्वारा अब तक २४,४६३ करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें२,६५१,७२७७ युवाओं को करियर मार्गदर्शन मिला। इन कार्यक्रमों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जहां जानकारी की कमी के कारण प्रतिभाएं पीछे छूट जाती थीं। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्धा कराने के लिए योगी सरकार ने 'सेवामित्र योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत कुशल कामगारों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक अ नलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर अब तक ५२,३४६ श्रमिक पंजीत हो चुके हैं। ये श्रमिक प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, एसी मैकेनिक, ब्यूटीशियन आदि सेवाओं के लिए लोगों को घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं। यह योजना एक ओर जहां श्रमिकों की आय सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश अब केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि श्रम और प्रतिभा का निर्यात करने वाला राज्य बन रहा है। आने वाले वर्षों में यह पहल राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

महिला की हत्या कर लूटपाट करने का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर। जिले की पुलिस ने एक महिला की हत्या कर उससे लूटपाट करने के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से महिला से लूटा गया मोबाइल फोन, आभूषण आदि बरामद किए गए हैं और आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी पप्पू उर्फ पप्पू मिस्त्री (२७) के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि तीन अगस्त को छपरौला गांव स्थित विद्या वर्ल्ड स्कूल के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, और उसके कुंडल, लौंग व मोबाइल फोन आदि लूट लिए थे। उन्होंने बताया, "मामले की जांच में पप्पू की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी।" अवस्थी ने बताया कि मंगलवार रात को बादलपुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास पुलिस जांच कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, "खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।" पुलिस उपायुक्त ने दावा किया कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।

अमेठी में सड़क दुर्घटना में निजी स्कूल शिक्षक की मौत

अमेठी। जिले के जायस थाना क्षेत्र में बुधवार को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ४२ वर्षीय निजी स्कूल शिक्षक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विवेक कुमार शुक्ला के रूप में हुई है जो बघेल में चक भूर गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि घटना सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने उस समय हुई जब शुक्ला कृष्णा नगर स्थित अपने ससुराल से घर लौट रहे थे। टक्कर में शुक्ला के सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में शिक्षक थे। जायस थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नवविवाहिता ने की खुदकुशी, दहेज उत्पीड़न का आरोप

मुजफ्फरनगर जिले में २६ वर्षीय नवविवाहिता ने रविवार को अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये एक कथित सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति, सास और नन्द पर दहेज की खातिर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में मयंक शर्मा की पत्नी गोल्डी अपने कमरे में मृत पाई गई। उनके मुताबिक, यह कदम उठाने से पहले महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया था। प्रजापत ने बताया कि कथित सुसाइड नोट में गोल्डी ने आरोप लगाया कि उसका पति, सास और नन्द दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे और इसी वजह से वह आत्महत्या कर रही है। उन्होंने बताया कि गोल्डी की शादी छह महीने पहले ही हुई थी। अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

नोएडा में एक सड़क हादसे में दो कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में दो कंपनी प्रतिनिधियों (डिलीवरी ब य) की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग-६१ पर नई बस्ती गांव के मोड़ पर उस वक्त हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार दो कंपनी प्रतिनिधियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर निवासी अंकित और बिहार के सीतामढ़ी निवासी राकेश के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टम र्टम के लिए भेज दिया गया है।

उन्नाव में आमने-सामने की भिड़ंत के बाद दो वाहनों में लगी आग, तीन लोगों की जलकर मौत

उन्नाव। जिले में बुधवार तड़के दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई, जिससे तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा तड़के करीब तीन बजे बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हरदोई-उन्नाव मार्ग पर मरी कंपनी मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब उन्नाव से हरदोई की ओर जा रहा एक डंपर की हरदोई से उन्नाव की ओर आ रही डीसीएम से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। थाना प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद छह बजे आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि हादसे में कानपुर देहात निवासी डंपर चालक पवन यादव, जालौन निवासी उसका सहायक सुमित, और संभल निवासी डीसीएम चालक महिपाल की जलकर मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि डीसीएम चालक का सहायक संभल निवासी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद

गंजमुरादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लगभग तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात बहाल किया गया।

अमेठी में मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने के कारण एक युवक की मौत

अमेठी। जिले में सोमवार को एक मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने के कारण एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गांव नौडाड के पास उस समय हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक सिद्धार्थनगर जा रहे थे तभी उनका दोपहिया वाहन सड़क किनारे पीपल के पेड़ से टकरा गया। थाना प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अब्दुल्ला (२८) के रूप में हुई। हादसे में घायल आलम को जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एआई के प्रयोग से योगी सरकार करेगी सख्ती

लखनऊ। योगी सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गड़बड़ी—मुक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की शक्ति का उपयोग करने की तैयारी में है। समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, छात्रवृत्ति और सामूहिक विवाह जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी को तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पेपरलेस, तेज और जवाबदेह बनाना भी है। योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से निपटने के लिए समाज कल्याण विभाग एआई— आधारित निगरानी तंत्र को अपनाने पर विचार कर रहा है। पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की मौजूदगी में 'एआई का समाज कल्याण की योजनाओं में उपयोग' विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस तकनीक के माध्यम से डाटा सत्यापन, लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं के कार्यान्वयन में सटीकता सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदारों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए पहले ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग को मजबूत किया गया है। छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों

को बार—बार पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर की व्यवस्था लागू की है। यह नई प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि पात्रों को बिना किसी रुकावट के योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी। एआई के उपयोग से इस प्रक्रिया में और अधिक सटीकता आएगी, जिससे फर्जी आवेदनों पर लगाम लगेगी और पात्रों को त्वरित लाभ मिलेगा। यही नहीं, डाटा विश्लेषण के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकें। एआई—आधारित सत्यापन प्रणाली से आवेदनों की जांच तेजी से होगी और फर्जी आवेदनों को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। योगी सरकार की इस पहल से समाज कल्याण विभाग की योजनाएं डिजिटल युग में एक नया मुकाम हासिल करेंगी। पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने से न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। एआई तकनीक के उपयोग से डाटा प्रबंधन, लाभार्थी सत्यापन और योजना निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम होंगी, बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार पर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार—बार इस बात पर जोर दिया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। एआई—आधारित निगरानी तंत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। समाज कल्याण विभाग जल्द ही इसकी विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप देगा।

सोनी सब के शो 'इत्ती सी खुशी' की शूटिंग के दौरान सुम्बुल तौकीर खान को अपनी बहन सानिया की माँ जैसी भूमिका निभाने की यादें ताजा हुई

मुंबई। १८ अगस्त को रात ६ बजे लॉन्च होने वाले सोनी सब के नए शो 'इत्ती सी खुशी' ने अपनी भावनात्मक कहानी और मजबूत

लीड कैरेक्टर के दमदार चित्रण से दर्शकों में उत्सुकता जगा दी है। शो की नायिका अन्विता दिवेकर का किरदार निभा रही हैं सुम्बुल तौकीर खान, जो एक दृढ़ निश्चयी युवती की भूमिका में दिखेंगी, जो परिवार की मुश्किलों को चुपचाप सहते हुए मजबूती से आगे बढ़ती है। शूटिंग के दौरान एक सीन फिल्माते वक्त सुम्बुल अपने निजी जीवन की यादों में खो गईं, जो उनके किरदार की भावनाओं से मेल खाती थीं। एक सिंगल पैरेंट के साथ पली—बढ़ीं सुम्बुल ने अपनी छोटी बहन सानिया के लिए हमेशा माँ जैसा स्नेह और देखभाल दिखाई, और उसके लिए हर वक्त मार्गदर्शक बनी रहीं। हाल ही में शूट किए गए एक दृश्य में, जहाँ अन्विता अपनी छोटी बहन को पढ़ाती और उसका होमवर्क करवाती नजर आती है, उस पल ने सुम्बुल को अपनी असल जिंदगी के उन पलों की याद दिला दी, जब सानिया हर छोटे—बड़े फैसले के लिए उनकी राय लेती थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से सहमति चाहता है। https://www-instagram-com/p/DNX31ÛwsRiT/\igsh¾MWoÛNmZvaGwwd3RhaQ==

अपनी इस खास याद को फैंस के साथ साझा करते हुए सुम्बुल ने इंस्टाग्राम पर लिखारू "कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो रील और रियल के बीच की सीमाएं मिटा देते हैं। 'इत्ती सी खुशी' में अन्विता के रूप में जब मैं अपने भाई—बहन को पढ़ाई में मदद कर रही थी, तो मुझे तुरंत अपनी असल जिंदगी की याद आई, जब मेरी छोटी बहन सानिया हर छोटे से छोटे फैसले के लिए मुझसे राय लिया करती थी बिलकुल वैसे ही जैसे बच्चा अपनी माँ से हाँ चाहता है।" 'इत्ती सी खुशी' देखना न भूलें १८ अगस्त से, हर सोमवार से शुक्रवार रात ६ बजे, सिर्फ सोनी सब पर।

स्क्रीन से दिल तकः 'इत्ती सी खुशी' में अन्विता के पारिवारिक संघर्षों में सुम्बुल तौकीर खान के जीवन की झलक

मुंबई। अपने लॉन्च से पहले ही सोनी सब का शो इत्ती सी खुशी अपनी भावनात्मक कहानी और मजबूत मुख्य किरदार अन्विता दिवेकर, जिसे सुम्बुल तौकीर खान निभा रही हैं, के कारण दर्शकों में जिज्ञासा जगा रहा है। यह शो अन्विता की कहानी हैं एक दृढ़ निश्चयी युवती की, जो अपने परिवार के संघर्षों का बोझ चुपचाप और मजबूती से उठाती है। सुम्बुल के सजीव अभिनय के साथ, यह किरदार दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ेगा, यह याद दिलाते हुए कि कभी—कभी परिवार को जोड़े रखने के लिए छोटे—छोटे प्रयास ही काफी होते हैं। हालांकि, अन्विता का किरदार एक काल्पनिक दुनिया से है, लेकिन उसकी आत्मा बेहद असल है और यह सुम्बुल के अपने जीवन में भी झलकती है। शो में, अन्विता छह भाई—बहनों में सबसे बड़ी है, जिसे माँ के त्याग और शराबी, गैर—जिम्मेदार पिता के सहारे रहना पड़ता है। वह अपनी जवानी, सपनों और आराम का त्याग कर भाई—बहनों की परवरिश

करती है, और अपनी मजबूती को कवच की तरह धारण करती है। वास्तविक जीवन में, परिस्थितियाँ भले अलग हों, लेकिन सुम्बुल की कहानी में भी वही जिम्मेदारी, भावनात्मक परिपक्वता और मौन साहस है। सुम्बुल के लिए अन्विता का किरदार निभाना एक बेहद निजी अनुभव रहा है। इस किरदार की भीतरी दुनिया उनके अपने जीवन के पहलुओं को दर्शाती है, जिससे यह भूमिका उनके दिल के बेहद करीब है। अन्विता के रूप में अभिनय करते हुए, सुम्बुल ने अपने जीवन के वे क्षण फिर से महसूस किए ँ शांत संघर्ष, अनकही जिम्मेदारियाँ और आगे बढ़ने का साहस। जैसे अन्विता ने समय से पहले ही माँ, सहारा और संरक्षक की भूमिका निभाई, वैसे ही सुम्बुल ने भी कम उम्र में भावनात्मक मजबूती विकसित की। एक सिंगल पैरेंट द्वारा पाली गई सुम्बुल ने अपने पिता और छोटी बहन का सहारा बनने के साथ—साथ, उनके सपनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इत्ती सी खुशी में अन्विता का किरदार निभा रहीं सुम्बुल तौकीर खान कहती हैं, "जिस तरह अन्विता अपने परिवार के दर्द को चुपचाप सहती है और उसे बोझ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानती है, वह मुझे गहराई से छूता है। यह किरदार न केवल मेरे अभिनय को चुनौती देता है, बल्कि मुझे अपने जीवन के कुछ अंश स्क्रीन पर लाने का दुर्लभ अवसर भी देता है। एक समय था जब जीवन अनिश्चित लग रहा था और मैं अपने पिता, बहन सानिया और परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रही थी। अन्विता की तरह, मैं मानती हूँ कि ताकत धैर्य से आती है, और यही दर्शन मैं अपने जीवन में जीती हूँ।" इत्ती सी खुशी देखें, सोमवार १८ अगस्त से, रात ६ बजे, केवल सोनी सब पर

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lat; ckt ib
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqj'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
C;jks phQ
eÅ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित। आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक